(iv) Basket for usage of rebateable oils has been expanded by the addition of solvent extracted sesame oil and salseed fat

(v) Government is exploring the possibility of import of stme quantity of edible oils.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की कमी

@1449. **श्री लक्खीराम अग्रवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में, विशेष रूप से गर्मी के दिनों में, पेयजल की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेयजल मिशन के अंतर्गत पेयजल की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) पेयजल मिशन के अंतर्गत इन क्षेत्रों के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से प्रावधान करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): 73 गांवों को छोड़कर शेष सभी "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पेयजल की सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं । "बिना जल स्रोत" वाले शेष समस्याग्रस्त गांवों को 1991-92 में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराये जाने का लक्ष्य बनाया गया है । मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में गर्मियों के महीनों के कुछेक इलाकों में पीने के पानी की कमी महसूस की गई है ।

(ख) और (ग) राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत शुरू की गई मिनी मिशन परियोजनाओं सहित केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर आधार पर स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जाते हैं । राज्य सरकार को रिलीज की गई त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की कम से कम 10 प्रतिशत धनराशि की आदिवासी जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल किया जाना है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत भी निधियों के ऐसे निर्धारण किए जाते हैं । स्वच्छ पेयजल सप्लाई का पहला जल स्रोत आदिवासी बस्तियों में स्थापित किया जाना होता है । बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए 1191.8 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली एक विशेष परियोजना अनुमोदित की गई थी 1991-92 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 2000 ऐसी बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने का भी प्रस्ताव है जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना का स्वरूप और आकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

1450. [*Transferred to the 10th September, 1991*].

Flats Constructed at Noida by A Force Housing Board

1451. SHRI M. PALANIYANDI:

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of DEFENCE pleased to state:

(a) whether it is a fact that J Force Housing Board, Race *Cava*

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 838, 6 सितम्बर, 1991 से स्थानान्तरित ।